Conservation of water, forest and land must for natural balance: Minister Patel

- Two-day workshop on subject 'Water, Forest and Land' begins at WALMI

■ **Staff Reporter**

MINISTER for Panchayat and Rural Development Kamleshwar Patel said that conservation of water, forest and land is necessary to prevent the deteriorating natural balance. This is possible through community participation. Patel was speaking at the two-day workshop on 'Re-Generating Natural Capital Land, Water and Forest' organised under the joint aegis of MP Water and Land Management Institute, Club of Rome International and Rajiv Gandhi Foundation.

Minister for Urban Development and Housing Jaivardhan Singh addressing a two-day workshop on 'Re-Generating Natural Capital Land, Water and Forest' organised under the joint aegis of MP Water and Land Management Institute, Club of Rome International and Rajiv Gandhi Foundation.

Minister Patel said that in the race for development, natural resources have been exploited indiscriminately in developed and developing countries including India. As a result, the existence of water, forest and land given by the nature has been endangered. He said that if we do not become conscious, the consequences will be dangerous. For this, the society should also come forward, he added. Water, forest and land are synonymous with each other: Minister for Public Relations P C Sharma said that water, forest and land, all three are synonymous with each other. Conformity among the three is

(Contd on page 2)

वाल्मी में जल, जंगल, जमीन विषय पर दो दिवसीय वर्कशॉप

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा प्राकृतिक संतुलन के लिए जल जंगल, जमीन का संरक्षण जरूरी

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि बिगड़ते हुए प्राकृतिक संतुलन को संवारने के लिये जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आवश्यक है। यह सामुदायिक भागीदारी से संभव है।

जल, जंगल और जमीन एक-दूसरे के पर्याय

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जल, जंगल, जमीन एक-दूसरे के पर्याय हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए सामंजस्य जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने कहा था कि भोपाल सुंदर है, इसे और सुंदर बनाएं।

मप्र जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ

जल, जंगल और जमीन बचाने हुआ विमर्श

भोपाल। नवदुनिया रिपोर्टर

मप्र जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) की ओर क्लब ऑफ रोम इंटरनेशनल संस्था एवं राजीव गांधी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जल, जंगल और जमीन को लेकर प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कलियासोत पहाड़ी स्थित वाल्मी संस्थान में किया गया, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ शामिल हुए।

जयवर्धन सिंह

कार्यशाला का उद्घाटन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के आथित्य में किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अरुण कुमार साहनी, लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह सांधू, डायरेक्टर राजीव गांधी फाउंडेशन विजय महाजन, डॉ.अशोक खोसला, संचालक वाल्मी उर्मिला शुक्ला सहित विभिन्न अतिथि उपस्थित रहे। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले दक्ष लोग सहभागी हुए जो मप्र में नीति निर्माण में सहयोग करेंगे। पहले दिन मुख्यत: जल का अधिकार, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण द्वारा बुंदेलखंड का विकास, गौशाला संवर्धन तथा गौशाला विकास सहित कई योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

कलियासोत इलाके में स्थित वाल्मी क्षेत्र के मॉडल का प्रदर्शनी में अवलोकन करते हुए आमंत्रित अतिथि। ● नवदुनिया

कुप्रबंधन की वजह से समस्याएं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कुप्रबंधन की वजह से आज जो समस्याएं निर्मित हो रही हैं उसके समाधान के लिए हमें आगे आना होगा। विकासशील देशों के साथ-साथ विकसित देशों में भी जल, जंगल, जमीन का दोहन तेजी से हो रहा है, परंतु भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए सरकार के साथ समाज को भी सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश में 378 निकायों में पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हो इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि नए विकास कार्यों को मंजूर करते समय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाएं। जनसंपर्क मंत्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जल को अधिकार के रूप में आम आदमी तक पहुंचाने की पहल की है, किंतु व्यक्ति विशेष का दायित्व भी बनता है की जल का सदुपयोग करें।

मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी अनुशंसा

कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए संचालक वाल्मी उर्मिला शुक्ला ने कहा कि हमारा संस्थान प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। हमने देश के अन्य थिंक टैंक के साथ पार्टनरशिप के तौर एमओयू साइन किया है जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कार्यशाला का समापन 28 अगस्त को होगा। इस कार्यशाला की अनुशंसा मुख्यमंत्री को प्रदान की जाएगी, ताकि जल, जंगल, जमीन के संदर्भ में व्यापक योजनाएं बनाई जा सकें।

जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के लिए समाज भी आए आगे

● जागरण रिपोर्टर ●

मप्र जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) द्वारा क्लब ऑफ रोम इंटरनेशनल संस्था एवं राजीव गांधी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जल-जंगल-जमीन की प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कलियासोत पहाड़ी स्थित वाल्मी संस्थान में किया गया, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ शामिल हुए।

कई योजनाओं पर हुआ विचार-विमर्श

कार्यशाला का उद्घाटन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के आथित्य में किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले एवं दक्ष लोग सहभागी हुए तथा मध्य प्रदेश की नीति निर्माण में सहयोग करेंगे, जिसमें मुख्यतः जल का अधिकार, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण द्वारा बुंदेलखंड का विकास, गौशाला संवर्धन तथा गौशाला विकास सहित कई योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आज कुप्रबंधन की वजह से जो समस्याएं निर्मित हो रही हैं उसके समाधान के लिए हमें आगे आना होगा। विकासशील देशों के साथ-साथ विकसित देशों में भी जल, जंगल, जमीन का दोहन तेजी से हो रहा है परंतु भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए सरकार के साथ समाज को भी सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

खास खबर | वाल्मी में जल, जंगल, जमीन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ

जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आवश्यक : पटेल

स्वदेश संवाददाता, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि बिगड़ते हुए प्राकृतिक संतुलन को संवारने के लिये जल, जंगल, जमीन का संरक्षण आवश्यक है। यह सामुदायिक भागीदारी से संभव है। उन्होंने यह बात म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, क्लब ऑफ रोम इंटरनेशनल संस्था तथा राजीव गांधी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 'री-जनरेटिंग नेचुरल कैपिटल लैण्ड, वाटर एण्ड फॉरेस्ट' पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में कहीं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भारत सहित अन्य विकसित और विकासशील देशों में विकास की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन किया गया है। इसका परिणाम है कि प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदत्त जल, जंगल, जमीन का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी हम नहीं चेते तो परिणाम भयावह होंगे। इसके लिये समाज को भी आगे आना चाहिए।

जल, जंगल और जमीन एक-दूसरे के पर्याय

जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जल, जंगल, जमीन तीनों एक-दूसरे के पर्याय है। पर्यावरण संतुलन के लिये तीनों में सामजस्य जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने भोपाल प्रवास के दौरान कहा था कि भोपाल बहुत सुन्दर शहर है, इसे और सुन्दर बनाने की आवश्यकता है। भोपाल शहर के मध्य स्थित तालाब, पहाड़, जंगल प्राकृतिक सौन्दर्य को दो-गुना करता है।

भू-जल पर निर्भरता कम करने की जरूरत

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि गत वर्षों में भू-जल के बिना सोचे-समझे दोहन ने गंभीर स्थिति निर्मित कर दी है। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए भू-जल पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है।